



अजमेर

Rashtradoot

फोन:- 2627612, 2427249 फ़ैक्स:- 0145-2624665

वर्ष: 36

संख्या: 151

प्रभात

अजमेर, मंगलवार 6 जनवरी, 2026

आर.जे./ए.जे./73/2015-2017

पृष्ठ 8

मूल्य 2.50 रु.

असम चुनाव, प्रियंका के लिए इम्तिहान की घड़ी बना

प्रियंका गांधी को असम चुनाव के लिए बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी प्रियंका गांधी के भक्त लोग, जैसे इमरान मसूद ही हैं

-रेणु मिश्रल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 जनवरी संभवतः यह पहला अक्सर है कि नेहरू-गांधी परिवार के किसी सदस्य को किसी चुनावी राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी दी गई है।

प्रियंका गांधी वाड़ा को असम के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जहाँ कांग्रेस का मुकाबला भाजपा और उसके नेता हेमंत बिस्वा शर्मा से है। हेमंत बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में थे, बाद में भाजपा में शामिल हुए और जल्दी ही भाजपा नेतृत्व के चहेते बन गए।

इस कमेटी में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी शामिल हैं, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से यह माँग की है कि प्रियंका गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए।

कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच प्रियंका गांधी को पार्टी में बड़ी भूमिका दिए जाने की माँग लगातार बढ़ती जा रही है। यह बात उन्होंने

■ लोकसभा में राहुल की अनुपस्थिति में, प्रियंका गांधी का प्रदर्शन बहुत सराहनीय रहा था और प्रियंका को पार्टी में महत्वपूर्ण व निर्णायक भूमिका देने की मांग जोरों से उठी है और यह बात सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तक भी पहुंचायी जा चुकी है।

■ अतः असम में प्रियंका गांधी और उनकी टीम यदि सफल होती है, तो उनकी अवहेलना करना मुश्किल हो जाएगा और प्रियंका गांधी असम में फेल हो जाती हैं तो उन्हें कोई और महत्वपूर्ण व निर्णायक भूमिका देने की मांग अपने आप ठंडी पड़ जाएगी।

■ यह सब समझते हुए, प्रियंका गांधी असम में यह जोखिम भरी जिम्मेवारी निभाने को क्यों तैयार हो गई? क्या वे कुछ निराशा सी हो गई थीं और जोखिम उठाने के अलावा उनके समक्ष कोई विकल्प नहीं रह गया था। “बोरियत”, का चक्रव्यूह तोड़ने के अलावा।

सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और यहाँ तक कि राहुल गांधी तक को साफ़-साफ़ बता दी है।

राहुल गांधी की अनुपस्थिति में

संसद में प्रियंका गांधी के शानदार प्रदर्शन ने इस धारणा को और मजबूत किया है कि उनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है जबकि वे भाजपा

और उसके नेतृत्व को चुनौती देने में पूरी तरह सक्षम हैं।

पार्टी में होने वाले संभावित फेरबदल में उनकी भूमिका क्या होगी, इस पर फिर से बहस शुरू हो गई है। यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें संगठन में कोई बड़ी और अहम जिम्मेदारी मिलेगी या चुनावी प्रबंधन से जुड़ी वह बड़ी भूमिका सौंपी जाएगी, जिसका वादा तो किया गया है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ।

पहले भी यह कहा जाता रहा है कि राहुल गांधी की टीम, प्रियंका गांधी को बड़ी भूमिका देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे राहुल गांधी की छवि दब सकती है या पार्टी के भीतर कोई वैकल्पिक शक्ति केन्द्र बन सकता है।

लेकिन सुनौं का कहना है कि पार्टी एक के बाद एक चुनाव हार रही है और राहुल गांधी अपनी बनाई हुई बिखरी हुई सी टीम के साथ अकेले पार्टी को संभाल पाने में असमर्थ दिख रहे हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘अब यही है मेरी जिंदगी’

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 5 जनवरी। पाँच साल जेल में रहने के बाद जब उनके लिए एक और दरवाज़ा बंद हो गया, तो सामाजिक कार्यकर्ता और जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर ख़ालिद ने अपनी महिला मित्र से कहा कि अब जेल में रहना ही उस की जिंदगी बन गई है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें खुशी है कि मामले में पाँच अन्य लोगों को ज़मानत मिल गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों की साज़िश के मामले में

■ सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज़ होने पर बेहद निराशा में उमर खालिद ने कहा, पर अन्य 5 को जमानत मिलने पर खुशी जताई।

ख़ालिद और उसके साथी छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम को ज़मानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ़ अपराधिक साज़िश में शामिल होने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। हालाँकि, कोर्ट ने इसी मामले में नामज़द पाँच अन्य लोगों, कार्यकर्ता गुलफ़िशा फ़ातिमा, मीरान हैदर, शिफ़ा उर रहमान, मोहम्मद सलीम ख़ान और शादाब अहमद को ज़मानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों की स्थिति ख़ालिद और इमाम के समान नहीं है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप ने क्यूबा, कोलंबिया और मैक्सिको को भी सैन्य कार्यवाही की धमकी दी

वेनेज़ुएला के सैन्य ऑपरेशन से ट्रंप बेहद उत्साहित हैं, उन्होंने कहा, अमेरिका पूरी तरह से तैयार है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 5 जनवरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपनी ताकत दिखाते हुए क्यूबा, कोलंबिया और मैक्सिको को कड़ी चेतावनी दी है, और आरोप लगाया है कि इन देशों की सरकारें मादक पदार्थों की तस्करी, गैंगवार और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे रही हैं। उनका कहना है कि वॉशिंगटन का धैर्य समाप्त हो रहा है, क्योंकि वेस्टर्न हैमिस्फीयर में सुरक्षा खतरों में इजाफा हो रहा है।

मार-ए-लागो से लौटते हुए एयरफ़ोर्स वन पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि यदि ये देश नशीली दवाओं के उत्पादन, सीमा पार अपराध और मादक पदार्थ तस्करी के गिरोहों के प्रभाव को नियंत्रित करने में विफल रहते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह से तैयार है और निर्णायक कार्रवाई करेगा।

क्यूबा पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, ट्रंप ने दावा किया कि वेनेज़ुएला में हाल की अमेरिकी कार्रवाई के बाद हवाना की स्थिति तेज़ी से कमज़ोर हुई है। उन्होंने

■ ट्रंप ने कहा, वेनेज़ुएला की मादुरो सरकार के पतन के बाद क्यूबा की कोई इनकम नहीं बची है और अब क्यूबा की सरकार भी गिर जाएगी, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत शायद ना पड़े।

■ ट्रंप ने कोलंबिया नेतृत्व पर कोकीन उत्पादन और अमेरिका में कोकीन बेचने का आरोप लगाया और सैन्य कार्यवाही का संकेत देते हुए कहा, अमेरिका ज्यादा दिन ऐसा नहीं होने देगा।

■ ट्रंप ने मैक्सिको के बारे में कहा कि ड्रग्स तस्करी के गिरोह ही मैक्सिको का शासन चला रहे हैं। वहाँ की राष्ट्रपति खुद ही भयभीत हैं। अगर मैक्सिको में हालात ठीक नहीं हुए तो हमारी सेना वहाँ जाएगी।”

कहा, यह एक प्रमुख आर्थिक लाइफलाइन के कटने जैसा है। ट्रंप ने कहा, “क्यूबा की अब कोई आय नहीं है,” उन्होंने आरोप लगाया कि “यह द्वीप राष्ट्र वेनेज़ुएला से तेल आपूर्ति पर अत्यधिक निर्भर था, उन्होंने अपनी सारी आय वेनेज़ुएला से प्राप्त की और अब क्यूबा सचमुच गिरने के कगार पर है।” ट्रंप ने तत्काल अमेरिकी सैन्य

हस्तक्षेप से इनकार किया, लेकिन उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि यहाँ भारी उटलफेर हो सकता है, हम इस देश में नहीं घुस रहे हैं। मुझे लगता है कि यह खुद गिरने वाला है। यह गिरने के लिए तैयार है।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि क्यूबा मूल के कई अमेरिकी ऐसे परिणाम का स्वागत करेंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उमर ख़ालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी जमानत

जमानत के लिए अपील करने पर भी एक साल की रोक भी लगाई

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 5 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 जनवरी 2025) को एक्टिविस्ट उमर ख़ालिद और शर्जील इमाम को 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। यह मामला गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें कथित “बड़ी साज़िश” का आरोप है।

लेकिन कोर्ट ने पाँच अन्य आरोपियों, गुलफ़िशा फ़ातिमा, मीरान हैदर, शिफ़ा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की कथित भूमिकाओं में अंतर होने के कारण उनकी जमानत मंज़ूर कर दी।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और एन.वी. अंबज़रिया की बेंच ने दोनों एक्टिविस्टों पर लगाये गये आरोपों की

■ सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साज़िश रचने के आरोप में हालांकि उमर ख़ालिद और शर्जील इमाम पर सख्ती की लेकिन 5 अन्य को जमानत दे दी और कहा कि पांचों की भूमिका स्पष्ट नहीं है।

■ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर ख़ालिद और शर्जील इमाम गवाहों की जाँच पूरी होने या वर्तमान आदेश की तारीख का एक वर्ष पूरा होने या इनमें से जो भी पहले हो उसके बाद ही फिर से जमानत याचिका दायर कर सकते हैं।

■ फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए साम्प्रदायिक दंगों में 53 लोग मारे गए थे तथा सैकड़ों घायल हो गए थे। इस मामले हाई कोर्ट पहले ही सभी आरोपियों की जमानत खारिज कर चुका था।

गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा कि ये दोनों एक्टिविस्ट अन्य आरोपियों की तुलना में अलग श्रेणी में खड़े हैं।”

सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2025

को इस मामले पर निर्णय सुरक्षित रखा था, जब इन आरोपियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 2 सितंबर के उस फैसले

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई भर्ती- डमी अभ्यर्थी बैठाने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार

जयपुर, 5 जनवरी। उपनिरीक्षक पुलिस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2021 में फर्जीबाड़े के एक बड़े मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसओजी ने परीक्षा में चयन कराने के लिए सहयोग करने वाले सुनील कुमार विश्नोई को गिरफ्तार किया है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि

■ गिरफ्तार आरोपी सुनील कुमार विश्नोई शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित उपनिरीक्षक पुलिस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2021 में डमी अभ्यर्थी बैठाने परीक्षा दिलाने और अवैध रूप से चयन कराने के संबंध

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप ने भारत के माल पर टैरिफ और बढ़ाने की धमकी दी

सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा, भारत जानता है कि वे “भारत द्वारा रूस से ऑयल खरीदने से मैं खुश नहीं हूँ और अगर मैं खुश नहीं हूँ, तो कभी भी टैरिफ बढ़ा सकता हूँ”

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 5 जनवरी। भारत पहले से ही अमेरिका की ओर से 50 प्रतिशत भारी टैरिफ का सामना कर रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने टैरिफ और बढ़ाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि “रूस से भारत द्वारा तेल खरीदने के कारण, वॉशिंगटन बहुत जल्दी नई दिल्ली पर टैरिफ बढ़ा सकता है।”

एयर फ़ोर्स वन विमान में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, “वे (भारत) असल में मुझे खुश करना चाहते थे। मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं, वे अच्छे ईमान हैं। उन्हें पता था कि मैं (भारत के रूसी तेल आयात से) खुश नहीं था और मुझे खुश करना ज़रूरी था। वे व्यापार करेंगे और हम उन पर

■ ट्रंप के साथ खड़े अमेरिका के सीनेटर लिन्डसे ग्रेहम ने ट्रंप का तर्क दोहराया और कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन के ग्राहकों पर दबाव बनाना ज़रूरी है।

बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। यह उनके लिए बहुत बुरा होगा।” ट्रंप को यह ताज़ा दिष्पणी, कई महीने पहले दिए गए उनके उमर दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें “आश्वासन दिया था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। अब कोई आयात नहीं होगा, वे तेल नहीं खरीद रहे हैं।”

भारत ने ट्रंप के इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच ऐसी

कोई बातचीत नहीं हुई थी। इधर, ट्रंप के साथ विमान में मौजूद अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि भारत पर लगाए गए टैरिफ ही “मुख्य कारण” हैं कि अब नई दिल्ली रूस से काफ़ी कम तेल खरीद रही है। उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ग्राहकों पर दबाव बनाना ज़रूरी है।

ग्राहम ने कहा कि एक महीने पहले जब उनकी मुलाक़ात भारतीय राजदूत से हुई थी, तो “वह केवल यही बात

करना चाहते थे कि भारत रूस से कम तेल खरीद रहा है। क्या आप राष्ट्रपति से टैरिफ हटाने के लिए कहेंगे।”

ग्राहम के दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन रूस से भारत के तेल आयात में गिरावट का रूझान ज़रूर दिख रहा है। भारत ने कहा है कि उसकी नीतियाँ बाज़ार में उपलब्ध विकल्पों और भारतीय उपमोक्ताओं की ज़रूरतों के आधार पर तय होती हैं।

हालाँकि हाल के महीनों में आयात घटा है, फिर भी रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने पहले आरोप लगाया था कि भारतीय कंपनियाँ रूस से खरीदे गए तेल को फिर से बेचकर अरबों डॉलर का मुनाफ़ा कमा रही हैं।

आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी के कुएं से गैस लीक

कोनसीमा, 05 जनवरी। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में ओएनजीसी के एक चालू तेल कुएं से बड़े पैमाने पर गैस लीक हो गई। इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना तब हुई, तब कुएं में कुछ समय के लिए

■ लीक हुई गैस में आग लगी, लोगों को बिजली का इस्तेमाल नहीं करने व चूल्हा नहीं जलाने के निर्देश।

प्रोडक्शन बंद होने के बाद वर्कओवर रिग का इस्तेमाल करके मरम्मत की जा रही थी।

मरम्मत के दौरान एक जोरदार धमाका हुआ और कच्चे तेल के साथ मिली हुई गैस भारी मात्रा में हवा में बहुत ऊपर तक चली गई। यह तेल का कुआं कोनासीमा के राजोल इलाके के इरसुमंडा गांव में है।

स्थानी अधिकारियों के मुताबिक,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

साल के पहले कार्यदिवस पर वकीलों ने पैरवी नहीं की

जयपुर, 5 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट में माह के दो शनिवार को कार्य दिवस घोषित कर मुकदमों की सुनवाई करने के निर्णय का वकीलों ने विरोध किया है। हाईकोर्ट में इस साल के पहले कार्यदिवस पर वकीलों ने मुकदमों में

■ वे इवनिंग कोर्ट के पायलट प्रोजेक्ट तथा माह में दो शनिवार कार्यदिवस घोषित होने का विरोध कर रहे हैं।

पैरवी नहीं की। निचली अदालत में इवनिंग कोर्ट आरंभ करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के विरोध में वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया और प्रकरणों में पैरवी नहीं की। ये दोनों निर्णय हाल ही में हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ की बैठक में लिए गए थे। इसके तहत हर माह के दो शनिवार को कार्य दिवस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हिंदुओं पर “अत्याचार” के खिलाफ हो रहे हल्ले व क्रोध का कोई असर नहीं है, बांग्लादेश के प्रशासन पर

एक नवीन घटना में एक हिंदू विधवा के साथ सरे मार पिटाई के बाद, कई बार बलात्कार हुआ, वह चीखती-चिल्लाती रही, पर, कोई बचाने नहीं आया

-अंजन राॅय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 5 जनवरी। भारत की भावनाओं और जन आक्रोश के बावजूद, बांग्लादेश हिंदू समुदाय की पीड़ा के प्रति पूरी तरह उपेक्षा बरत रहा है।

बांग्लादेश ने भारत की बार-बार की अपीलों और वहाँ हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर आम लोगों की गहरी पीड़ा की भावनाओं पर बहुत कम ध्यान दिया है।

हाल की एक घटना में, एक हिंदू विधवा का पीछा किया गया, उसे परेशान किया गया और बाद में दो लोगों ने उसकी गुहार की अनदेखी करते हुए, उसे पकड़कर प्रताड़ित किया। स्थानीय

प्रशासन ने भी उसे सुरक्षा देने के लिए प्रयास नहीं किए।

आखिरकार उसके पीछा करने वालों ने उसे पकड़ लिया, उसे बेरहमी से यातनाएँ दीं, पेड़ से बाँध दिया और उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। बाद में स्थानीय लोगों ने उसे बेहोशी की हालत में पाया और उसे एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। उसका इलाज शुरू होने और होश में आने के बाद ही उसकी पीड़ा और दुर्गति की पूरी जानकारी सामने आ सकी।

महिला पर हुए इस भयानक हमले का खुलासा होने के बाद ही पुलिस ने कुछ कदम उठाए और दो अपराधियों को गिरफ्तार किया। वह इतनी डरी हुई थी कि उसने शुरू में अपनी ओर से कुछ

■ डर इतना व्याप्त था कि उस महिला को रिपोर्ट लिखाने की हिम्मत नहीं हुई। पर, अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी दुर्दशा देखकर, घटना सामने आई।

■ हंगामा बढ़ता देख पुलिस हरकत में आई और दो अपराधियों को गिरफ्तार किया।

■ दूसरी ओर, बांग्लादेश के खिलाड़ी को आईपीएल मैचों से बाहर करने के बाद, आईपीएल मैचों के बांग्लादेश में प्रसारण पर रोक लगाई। पर, इसका कोई असर नहीं रहा, क्योंकि, भारत में ही इन मैचों की “व्यूअरशिप” इतनी है कि आईपीएल मैच की लोकप्रियता पर बांग्लादेश की रोक का कोई महत्व नहीं दिख रहा।

भी बताने की हिम्मत नहीं की। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए डर और धमकाने का

ऐसा ही माहौल बना हुआ है। जैसे-जैसे ऐसी घटनाओं और

अत्याचारों के समाचार आ रहे हैं, भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार की बांग्लादेश के हिंदुओं की दुर्दशा एवं पीड़ा के प्रति निष्क्रियता को लेकर निराशा आमजन में बढ़ती जा रही है। कुछ लोग यह भी याद दिला रहे हैं कि अमेरिका दुनिया भर में अपने नागरिकों और अपने हितों की रक्षा के लिए कितने सख्त और सक्रिय कदम उठाता है।

अमेरिकी नीतियों की तुलना में भारत दम्बूपन का रवैया अपना रहा है और पड़ोसी देशों में हिंदुओं की रक्षा करने की अपनी क्षमता को लगभग विल्कुल भी नहीं दर्शा रहा है।

इस बीच, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल टीम

से बाहर करी जाने के फ़ैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, बांग्लादेश सरकार ने अपने देश में आईपीएल मैचों के प्रसारण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इसका आईपीएल मैचों या उनकी लोकप्रियता पर ज़्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है। भारत में दर्शकों की संख्या ही आईपीएल को ऊँची टीआरपी दिलाने के लिए काफ़ी है। बांग्लादेश द्वारा आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाने के निर्णय पर भारत ने अभी तक कोई औपचारिक टिप्पणी नहीं की है।

खिलाड़ी चयन के पूरे मुद्दे को इन्टरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के संज्ञान में भी लाया गया है। आईसीसी का मैच स्थलों, अलग-अलग

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)